

अनुदान संख्या 11 - उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

GRANT No. 11 - DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	6548,93,00		
		6549,01,00	4706,16,67	-1842,84,33
पूरक	Supplementary	8,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1839,33,34
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	1651,70,00		
		1662,32,00	1655,88,64	-6,43,36
पूरक	Supplementary	10,62,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			6,43,25

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए: -

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	19715.00		
पू.	S.	1.00	22055.55	22055.28
पु.	R.	2339.55		-0.27

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष मुख्य शीर्ष “2070” अन्य प्रशासनिक सेवायें	Head Major Head “2070” Other Administrative Services			
मू.	O.	6410.00		
पू.	S.	1.00	5704.01	5702.67
पु.	R.	-706.99		-1.34
मुख्य शीर्ष “2552” उत्तर पूर्व क्षेत्र	Major Head “2552” North Eastern Areas			
मू.	O.	209458.00		
पू.	S.	2.00
पु.	R.	-209460.00		..
मुख्य शीर्ष “2852” उद्योग	Major Head “2852” Industries			
मू.	O.	102101.00		
पू.	S.	1.00	107951.51	107669.33
पु.	R.	5849.51		-282.18
मुख्य शीर्ष “2885” उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head “2885” Other Outlays on Industries and Minerals			
मू.	O.	284036.00		
पू.	S.	1.00	304835.51	304835.44
पु.	R.	20798.51		-0.07
मुख्य शीर्ष “3475” अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head “3475” Other General Economic Services			
मू.	O.	33173.00		
पू.	S.	2.00	30421.08	30353.95
पु.	R.	-2753.92		-67.13

(I) छह शीर्षों के अंतर्गत – ₹219191.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹219114.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे:

(का) मुख्य शीर्ष “2552” –

(क) “तकनीकी शिक्षा – अन्य व्यय – स्वायत्त शासी निकायों को परियोजना आधारित सहायता” – ₹1500.00 लाख;

(ख) “पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का विकास – सहायिकी” –

(i) “पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का औद्योगिक विकास” – ₹64996.00 लाख (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(ii) “जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और सिक्किम सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में अवस्थित इकाईयों को माल और सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता” – ₹142888.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(खा) मुख्य शीर्ष “2885” – “पिछड़े क्षेत्रों का विकास – राजसहायता – लद्दाख का औद्योगिक विकास, 2022” – ₹9730.00 लाख मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “संबद्ध कार्यालय – आर्थिक सलाहकार (डी. पी. आई. आई. टी.)” के अंतर्गत – ₹1387.99

(I) Provision of ₹219191.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024) remained wholly unutilized under six heads; of these ₹219114.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2552” -

(a) “Technical Education - Other Expenditure - Project Based Support to Autonomous Bodies” - ₹1500.00 lakhs;

(b) “Development of Backward Areas - Subsidies” -

(i) “Industrial Development of Backward and Remote Area” - ₹64996.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs); and

(ii) “Budgetary support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim” - ₹142888.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head “2885” - “Development of Backward Areas - Subsidies - Industrial Development of Ladakh, 2022” - ₹9730.00 lakhs - due to non-approval of scheme by the Cabinet.

(II) Under Major Head “3451” - “Attached Offices - Economic Adviser (DPIIT)” - saving of

लाख की बचत (₹3493.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जी-20 शिखर सम्मेलन में कम व्यावसायियों को लेने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2070” – “विस्फोटक – पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी. ई. एस. ओ.)” के अंतर्गत – ₹708.33 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6411.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्टाफ की पदोन्नति नहीं होने और इंटरनेट लीज लाइन के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2852” – “उपभोक्ता उद्योग – अन्य – नमक आयुक्त” के अंतर्गत – ₹1943.51 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5150.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुंबई क्षेत्र में एस. सी. ओ. भूमि के सर्वेक्षण और सीमांकन के कार्य को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और विभाग बंद हो जाने के कारण कम संख्या में व्यवसायियों को लेने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2885” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:-

(का) “पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी – संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017” – ₹1464.32 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “औद्योगिक गलियारा – दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा – राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एन. आई. सी. डी. आई. टी.)” – ₹196463.60 लाख की बचत (₹200000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “3475” – “पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्को का विनियमन – बौद्धिक संपदा” के अंतर्गत – ₹2793.09

₹1387.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3493.00 lakhs) was due to hiring of less professionals in G-20 Summit.

(III) Under Major Head “2070” - “Explosives - Petroleum and Explosive Safety Organisation (PESO)” - saving of ₹708.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6411.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to non-promotion of staff and non-finalisation of proposal for internet lease line.

(IV) Under Major Head “2852” - “Consumer Industries - Others - Salt Commissioner” - saving of ₹1943.51 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5150.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to non-finalisation of survey and demarcation work of SCO land in Mumbai region and hiring of less professionals owing to closure of the Department.

(V) Under Major Head “2885” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Development of Backward Areas - Subsidies - Industrial Development Scheme 2017 for UT of J&K and UT of Ladakh” - saving of ₹1464.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs); and

(B) “Industrial Corridors - Delhi Mumbai Industrial Corridor - National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT)” - saving of ₹196463.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(VI) Under Major Head “3475” - “Regulation of Patents, Designs and Trade Marks - Intellectual

लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹31307.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, स्टाफ़ की संख्या में कटौती किए जाने और आई. टी. उपकरणों की कम संख्या में खरीद होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹239012.88 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग” – ₹3727.46 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3727.27 लाख हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2852” – “सामान्य” –

(क) “औद्योगिक संवर्धन – मेक इन इंडिया” – ₹3600.58 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3358.84 लाख हुआ।

(ख) “स्वायत्त शासी निकायों को सहायता – स्वायत्त शासी संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता” – ₹3228.42 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3188.41 लाख हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “2885” – “पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी” –

(क) “पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का विकास” – ₹70102.02 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹70101.99 लाख हुआ।

(ख) “जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और सिक्किम सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में अवस्थित इकाईयों को माल और सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता” – ₹146467.02 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹146467.

Property” - saving of ₹2793.09 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹31307.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024) was due to receipt of less proposals, reduction of staff strength and less procurement of IT equipments.

2.(I) The above savings were partly (₹239012.88 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹5.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under the following major heads:-

(A) Major Head “3451” - “Secretariat - Department for Promotion of Industry and Internal Trade” - ₹3727.46 lakhs. Actual excess, however, was ₹3727.27 lakhs.

(B) Major Head “2852” - “General” -

(a) “Industrial Promotion - Make in India” - ₹3600.58 lakhs. Actual excess, however, was ₹3358.84 lakhs.

(b) “Assistance to Autonomous Bodies - Project Based Support to Autonomous Institutions” - ₹3228.42 lakhs. Actual excess, however, was ₹3188.41 lakhs.

(C) Major Head “2885” - “Development of Backward Areas - Subsidies” -

(a) “Industrial Development of Backward and Remote Area” - ₹70102.02 lakhs. Actual excess, however, was ₹70101.99 lakhs.

(b) “Budgetary Support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim” - ₹146467.02 lakhs.

01 लाख हुआ।

(ग) “हिमाचल प्रदेश (एच. पी.) और उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017” – ₹9999.89 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹9999.88 लाख हुआ।

(घ) “संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर का औद्योगिक विकास” – ₹1887.49 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1887.48 लाख हुआ।

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष “2852” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:

(का) “उपभोक्ता उद्योग – चमड़ा – फुटवियर चमड़ा और आनुषांगिक विकास कार्यक्रम” – ₹834.99 लाख का अधिक व्यय (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपेक्षाकृत अधिक संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(खा) “सामान्य – अन्य व्यय – व्हाइट गुड्स (ए. सी. और एल. ई. डी लाइटों) के लिए उत्पादन सह प्रोत्साहन योजना” – ₹919.58 लाख का अधिक व्यय (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपेक्षाकृत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (₹643.36 लाख) दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1062.00 लाख के पूरक अनुदान का 61 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से कम थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:—

Actual excess, however, was ₹146467.01 lakhs.

(c) “Industrial Development Scheme for the State of Himachal Pradesh (HP) & Uttarakhand, 2017” - ₹9999.89 lakhs. Actual excess, however, was ₹9999.88 lakhs.

(d) “Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir” - ₹1887.49 lakhs. Actual excess, however, was ₹1887.48 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2852” - under the following heads:-

(A) “Consumer Industries - Leather - Footware, Leather and Accessories Development Programme” - excess of ₹834.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to receipt of more claims.

(B) “General - Other Expenditure - Production Linked Incentives for White Goods (ACs and LED Lights)” - excess of ₹919.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs) was due to receipt of more proposals.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹643.36 lakhs) constituted 61 percent of the supplementary grant of ₹1062.00 lakhs obtained in December, 2023 and less than 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
मुख्य शीर्ष “4059”	Major Head “4059”			
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	1100.00		
पू.	S.	1061.00	1908.57	1908.55
पु.	R.	-252.43		-0.02

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) मुख्य शीर्ष “4059” – “कार्यालय भवन – निर्माण – पेटेंट और ट्रेड मार्क महा नियंत्रक के कार्यालय (आई. डी. सी. जी. पी. डी. टी. एम.) में अवसंरचना विकास” के अंतर्गत – ₹1100.00 लाख का मूल प्रावधान ₹1061.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2161.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, आई. पी. ओ. भवन के पुनरुद्धार के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कम संख्या में आई. टी. उपकरणों की खरीद किए जाने के कारण ₹252.45 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹399.89 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 98 प्रतिशत थी।

(I) Under “Office Buildings - Construction - Infrastructure Development in Controller General of Patents and Trade Marks (IDCGPDTM)” - the original provision of ₹1100.00 lakhs was augmented to ₹2161.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1061.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹252.45 lakhs - due to non-finalisation of proposal for renovation of IPO Building and procurement of less IT equipments.

(II) Under one head saving of ₹399.89 lakhs occurred constituting 98 percent of the sanctioned provision.